their preliminary evaluation study report are as follows :—

(i) The all India figures regarding funetionalty are as follows :—

Statement 'A'

Year	% of functional Chulha		Total
Installation of Improved Cookstove	Functional (In use)	Functional (But not in use)	
1988-89	42.6	4.9	47.5
1989-90	54.0	4.2	58.2
1990-91	55.6	4.7	60.3

(ii) (a) Functionality of chulhas is going up year after year due to technological improvement.

(b) The functionality in respect of old chulhas is less as chulhas do not have unlimited life.

(iii) On an all India basis 19.3 *';b* chulhas are reported to be not working but they are existing. They can be probably put to use by repair and maintenance.

(iv) The fixed and portable chulhas are 1.38 and 1.48 times more efficient respectively than the traditional chulhas.

Filling of SC/ ST quota in Civil Services

@1297. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the total number of vacancies yet to be filled under Scheduled Castes/Scheduled Tribes quota of IAS and allied services;

(b) by when these are likely to be filled together with reasons for their being left unfilled till now; and

(c) whether Government have fixed responsibility for not fulfilling the quota provision *I*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) and (b) A statement is placed on the Table of the House. *(See below).*

(c) Does not arise.

©Previously Unstarred Question 271, transferred from 24th February, 1993.

As per Civil Services Examination, 1991, 871 vacancies (656 General, 138 SC and 77 ST) were to be filled in various Services. Candidates were allotted as per the details given below :

Statement

Service	General		SC		ST	
	Vacancy	Allotted	Vacancy	Allotted	Vacancy	Allotted
IAS	62	62	12	12	6	6
Indian Foreign Service	9	9	2	2	1	1
IPS	62	62	12	12	6	6
Other Group 'A' & Group 'B' Services	523	453	112	105	64	49
Unfilled Gap	—	70	—	7	—	15

From the table it can be seen that reserved vacancies to an extent of 7 in the case of SC and 15 in'the case of ST remain to be filled: These vacancies remain unfilled due to the following reasons :

(1) Candidates ineligible as per Rule 17 of C.S.E. Rules, and not allotted to any service;

(2) Candidates who declined service;

(3) Candidature cancelled on medical-reasons;

(4) Candidates who were otherwise not eligible, obtained interim orders from Central Administrative Tribunal to ap pear in the Examination and were not allotted any service.

In order to fill up these vacancies, a re-quisition has been placed with the UPSC . to release a Supplementary List.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते का बंद किया जाना

@@1298. **श्री अनन्त राम कायसवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ता न देने की सिफारिश की थी और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्णरूपेण अनु-पालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) 1987-88 से 1991-92 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में मंत्रालय-वार कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) क्या सरकार वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए समयोपरि भत्ते को पूर्णत बंद किया जाना सुनिश्चित करेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) तथा (ख) सरकार ने आरम्भ में केन्द्रीय सरकार के कर्म-चारियों को समयोपरि भत्ता न देने के संबंध में चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली थी । तथापि, तदनन्तर, प्रचालक श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में जो आवश्यक सेवाएं बनाए रखते हैं तथा प्रशासनिक स्टाफ के कुछ वर्गों के संबंध में भी सेवा की अत्या-वश्यकता के आधार पर समयोपरि भत्ता बंद करना संभव नहीं था । अत: समयोपरि भत्ते को जारी रखने का निर्णय किया गया . तथा संशोधित वेतनमानों के संदर्भ में समयोपरि भत्ते के भुगतान के आदेश जारी किए गए ।

(ग) वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं । (नीचे देखिए)

(घ) किफायत करने के उपाय के तौर पर सभी मंत्रालयों/विभागों को कहा गया है कि :

(1) कार्यालय समय के दौरान स्टाफ की सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करें ताकि स्टाफ को समयोपरि कार्य पर बैठाने की आवश्यकता में कमी लाई जा सके, तथा

(2) यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 1992-93 के दौरान तथा इसके बाद में समयोपरि भत्ते पर व्यय वर्ष 1991-92 के दौरान इस प्रयोजन के लिए हुए व्यय से अधिक न होने पाए ।

@@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 117, 23 फरवरी से स्थानांतरित ।